



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2011/चैत्र 28, 1933

No. 211]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2011/CHAITRA 28, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 327(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अंतर्गत मानव संसाधन विकास महानिदेशालय के सृजन से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को जारी रखते हुए भारत के राष्ट्रपति 18 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792/2008 के माध्यम से मानव संसाधन विकास महानिदेशालय को पहले ही सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त अनुदान संख्या 43-अप्रत्यक्ष कर के बारे में निम्नलिखित कार्यों के करने के लिए उस में एक व्यय प्रबंधन सेल (ई एम सी) के सृजन की अनुमति देते हैं :

- (i) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बजट परिपत्र जारी करना;
- (ii) अनुदान के अंतर्गत विभिन्न संघटक कार्यालयों/यूनिटों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच करना;
- (iii) बजट अभ्यास की प्रत्येक अवस्था पर अर्थात् बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आर ई) तथा अंतिम जरूरत, स्थिति को समेकित करना तथा उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए वित्तीय सलाहकार (वित्त) को प्रस्तुत करना;
- (iv) अपने-अपने बजट नियंत्रण प्राधिकारियों को उद्देश्य शीर्षवार अनुमोदित उपबंधों का आवंटन करना;
- (v) संगत बजट दस्तावेजों में शामिल करने हेतु बजट अनुमान विवरण (एस सी ई) तैयार करना;

(vi) व्यय के साथ-साथ स्वीकृत अनुदान में प्रगति की मॉनिटरिंग करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए मासिक तथा तिमाही व्यय समीक्षा वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत करना;

(vii) सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन के लिए पुनर्नियोजन आदेशों, बजट का अभ्यर्पण आदि का वित्तीय सलाहकार (वित्त) को प्रस्ताव करना;

(viii) प्रधान सीसीए, सीबीईसी के साथ विचार-विमर्श करके विनियोजन लेखों को अंतिम रूप देना तथा वित्तीय सलाहकार (वित्त) को सहमति के लिए प्रस्तुत करना;

(ix) विस्तृत अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करना;

(x) व्यय मामलों में लेखा परीक्षा संदर्भों के बारे में कार्रवाई करना, उदाहरणार्थ लेखा परीक्षा पैरों/पीएसी पैरों आदि पर कृत कार्रवाई की टिप्पणी;

(xi) उपरोक्त से जुड़ा अन्य कोई मामला ।

2. व्यय प्रबंध सैल को अनुदान सं. 43-अप्रत्यक्ष करों के तहत सभी बजट मामलों के संबंध में नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव किया जाता है और यह इस अनुदान के तहत व्यय बजट के प्रबंध से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेगा ।

3. व्यय प्रबंधन सैल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड की डी जी एच आर डी, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एक अपर महानिदेशक (एच आर एम) द्वारा अध्यक्षता किए जाने का प्रस्ताव है, जो सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के स्तर का अधिकारी होगा और नई दिल्ली में नियुक्त होगा । व्यय प्रबंधन सैल को दिनांक 1-4-2011 से प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है ।

4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड में व्यय प्रबंधन सैल की कर्मचारी आवश्यकता को सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्वीकृत कर्मचारी क्षमता में से पूरा किया जाएगा।

5. अतः, अब से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के तहत बजटीय प्राधिकारी अपने बजटीय अनुमान/संशोधित अनुमान व्यय प्रबंध प्रकोष्ठ को भेजेंगे। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के तहत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों को वार्षिक बजट/संशोधित बजट के आबंटन से संबंधित आदेश अपर महानिदेशक (एच आर एम विंग), की अनुमति से डीजीएचआरडी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामांकित संयुक्त आयुक्त के स्तर अथवा उससे ऊपर के किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

[फा. सं. ए-11013/28/2007-प्रशा-IV]

के. के. खट्टर, उप-सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2011

**G.S.R. 327(E).**—In continuation to the Government of India Notification No. G.S.R. 792(E), dated 18th November, 2008, regarding creation of Directorate General of Human Resource Development under Central Board of Excise and Customs (CBEC), the President of India is pleased to approve the creation of Expenditure Management Cell (EMC) in the Directorate General of Human Resource Development for attending to the following functions in respect of Grant No. 43—Indirect Taxes, in addition to those already assigned through notification No. G.S.R. 792/2008, dated 18-11-2008:

- (i) To issue the Budget Circular as prescribed by the Budget Division, Department of Economic Affairs;
- (ii) To examine the Budget proposals received from various constituent formations/units under the Grant;
- (iii) To consolidate the position at each stage of the Budget exercise i.e. Budget Estimates (BE), Revised Estimates (RE) and Final Requirement (FR) and submit the same to FA (Finance) for further action;
- (iv) To allocate object head-wise approved provisions to respective Budget controlling authorities;

- (v) To prepare the Statement of Budget Estimates (SBEs) for inclusion in the relevant Budget documents;
- (vi) To monitor the progress in Expenditure vis-a-vis Sanctioned Grant and submit the Monthly and Quarterly Expenditure Review to FA (Finance) for further action;
- (vii) To propose Re-appropriation orders, surrender of savings etc. to FA (Finance) for concurrence/approval of the competent authority;
- (viii) To finalize the Appropriation Accounts in consultation with Principal CCA, CBEC and submit to FA (Finance) for concurrence;
- (ix) To take necessary action in respect of the examination by the Standing Committee on Finance on Detailed Demands for Grants;
- (x) To take action in respect of Audit references in Expenditure matters, for example Action Taken Notes on Audit Paras/PAC Paras, etc.
- (xi) Any other matter, related to the above.

2. The Expenditure Management Cell is proposed to act as the nodal authority in respect of all Budget matters under Grant No. 43—Indirect Taxes and will perform all work related to management of Expenditure Budget under this Grant.

3. The Expenditure Management Cell, CBEC, is proposed to be headed by an Additional Director General (HRM) under DGHRD, Customs and Central Excise, who will be an officer of the level of Commissioner of Customs and Central Excise and will be located at New Delhi. The EMC is proposed to be made operation w.e.f. 1-4-2011.

4. The Staff requirement of the Expenditure Management Cell in CBEC will be met from within the sanctioned strength of the Customs and Central Excise Department.

5. The Budgetary Authorities under CBEC will, henceforth, be required to send their annual Budgetary Estimates/Revised Estimates to the Expenditure Management Cell. The order related to allocation of the annual Budget/revised Budget to the field formations under CBEC are proposed to be issued by the Additional Director General (HRM Wing), DGHRD, or, any other officer not below the rank of Joint Commissioner nominated for this purpose by the DGHRD with the approval of the Member (P & V).

[F. No. A. 11013/28/2007-Ad. IV]

K. K. KHATTAR, Dy. Secy.